नागरिक विविध
न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और प्रेम चंद जैन के समक्ष,
महेश चंद, वादी।
बनाम

पूरन चंद और अन्य,-प्रतिवादी।
1967 का सिविल विविध क्रमांक 4267
1967 का सिविल मूल क्रमांक 1
30 जुलाई 1968.

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X)-धारा 17-न्यायालय-फीस अधिनियम (1870 का VII)-धारा 11-साझेदारी के विघटन और खातों के प्रतिपादन के लिए मुकदमा-विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा गया-निर्णय ने न्यायालय का नियम बनाया-इस पर आधारित डिक्री पुरस्कार - क्या तब तक जारी किया जा सकता है जब तक कि वास्तव में भुगतान की गई अदालती फीस और देय शुल्क के बीच का अंतर पूरा न हो जाए।

माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो या तो आवश्यक निहितार्थ से या विशेष रूप से, कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को ओवरराइड करता हो। किसी मुकदमे में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत एक डिक्री कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 11 की शर्तों के तहत एक डिक्री है। किसी मुकदमे में पुरस्कार पर आधारित डिक्री मुकदमे में एक डिक्री है। यह एक डिक्री है जो मुकदमे को समाप्त कर देती है; और, इसलिए, धारा 11 के प्रावधान लागू होंगे और डिक्री तभी तैयार की जाएगी जब वास्तव में भुगतान की गई अदालती फीस और देय फीस के बीच अंतर हो। हालाँकि, न्यायालय के बाहर किसी संदर्भ में किसी पुरस्कार के आधार पर पारित डिक्री के लिए न्यायालय शुल्क स्टांप की आवश्यकता नहीं होती है और धारा 11 उस पर लागू नहीं होती है।

[पैरा 5 और 6]

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 29 मार्च, 1968 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, और अंततः इसका निर्णय 30 जुलाई, 1968 को माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.सी.जैन की खंडपीठ द्वारा किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 10 के तहत निष्पादन के लिए आवेदन जिसमें प्रार्थना की गई कि निर्णय-ऋणी को 54069 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए आर. एन. एम. इत्तल और एस. के. स्याल वकील।

सिरी निवास प्रतिवादी के लिए एच. एल. सोनी और पूरन सिहंद वकील।

डिवीजन बेंच का फैसला

न्यायमूर्ति महाजन, -इस सवाल के महत्व को देखते हुए मेरे द्वारा यह मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था,

(2) सटीक प्रश्न, जिसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या एक मुकदमा, जिसमें मध्यस्थता का संदर्भ है और निर्णय पर एक डिक्री का पालन किया जाता है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत न्यायालय का नियम बना दिया जाता है, न्यायालय-फीस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा ?

(3) यह प्रश्न विषम परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है। डिक्री धारक ने निर्णय-देनदार के खिलाफ साझेदारी के विघटन और खातों के प्रतिपादन के लिए मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा अधीनस्थ न्यायाधीश, अम्बाला की अदालत में लंबित था और स्थानांतरण द्वारा इस अदालत में लाया गया था। मुकदमे में विवाद, पक्षों की सहमति से मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ ने अपना निर्णय दिया और पक्षों की आपत्तियों को सुनने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत निर्णय को न्यायालय का नियम बना दिया गया।

(4) हालाँकि, कार्यालय ने कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के मद्देनजर डिक्री नहीं बनाई। वादी डिक्री धारक और प्रतिवादियों में से एक, जिनके पक्ष में फैसला आया है, ने उन्हें दी गई राशि की वसूली के निष्पादन के लिए एक आवेदन दिया है। निर्णय-देनदारों ने आपत्ति उठाई है कि कोई डिक्री नहीं है और जब तक कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी डिक्री नहीं निकाली जा सकती है, अर्थात् भुगतान की गई कोर्ट-फीस और अपेक्षित कोर्ट-फीस में अंतर पर शुल्क की भरपाई पर राहत की जाती है। यह वह आपत्ति है जो इन कार्यवाहियों में निर्धारण के लिए आती है। जब मामला 29 मार्च 1968 को मेरे सामने पोस्ट किया गया, मुझे संदेह था कि धारा 11 के प्रावधान इस तरह के डिक्री पर लागू होंगे या नहीं। यही कारण था कि मैंने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया; और इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।

(5) पार्टियों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, मेरा विचार है कि निर्णय-देनदारों की आपत्ति अच्छी तरह से आधारित है और प्रबल होनी चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो या तो आवश्यक निहितार्थ से या विशेष रूप से, धारा 11 के प्रावधानों को ओवरराइड करता है। श्री आर.एन.मित्तल, जो डिक्रीधारक के लिए उपस्थित होते हैं, का तर्क है कि न्यायालय के बाहर एक संदर्भ में धारा 11 के तहत एक डिक्री होती है जिसमे कोर्ट-फीस स्टांप की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी मुकदमे में डिक्री के लिए कोर्ट-फीस की आवश्यकता नहीं होती है जब यह एक पुरस्कार-डिक्री है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत पारित की जाती है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं. न्यायालय-फीस अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार है-
"मध्यम लाभ के लिए या अचल संपत्ति और मध्य लाभ के लिए, या किसी खाते के लिए मुकदमे में, यदि लाभ या डिक्री की गई राशि उस राशि के दावे किए गए लाभ से अधिक है जिस पर वादी ने मांगी गई राहत का मूल्यांकन किया है, तो डिक्री तब तक जारी नहीं होगी जब तक कि वास्तव में भुगतान की गई फीस और उस फीस के बीच का अंतर जो देय होता, यदि मुकदमे में पूरा लाभ या इस प्रकार डिक्री की गई राशि शामिल होती, उचित अधिकारी को भुगतान नहीं किया जाता।
जहां डिक्री के निष्पादन के दौरान आंतरिक लाभ की राशि सुनिश्चित की जानी बाकी है, यदि इस प्रकार सुनिश्चित किया गया लाभ दावा किए गए लाभ से अधिक है, तो डिक्री का आगे का निष्पादन तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि वास्तव में भुगतान की गई फीस और शुल्क जो देय होता है के बीच का अंतर,

यदि मुकदमे में इस प्रकार सुनिश्चित किए गए लाभ का पूरा हिस्सा शामिल होता, का भुगतान किया जाता है। यदि अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा।"

और इसमें केवल विशेष रूप से उल्लिखित मामलों को शामिल किया गया है, यहां तक कि किसी मुकदमे में भी। वर्तमान डिक्री निस्संदेह एक मुकदमे में पारित की गई थी। अंतर केवल इतना था कि न्यायालय द्वारा विवाद का निर्धारण करने के बजाय, पक्षों की सहमति से, मंच को बदल दिया गया था; और मध्यस्थ द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, जिस पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत न्यायालय का नियम बना दिया गया था; और उस प्रावधान के संदर्भ में एक डिक्री का पालन करना था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी मुकदमे में धारा 17 के तहत कोई डिक्री कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 11 की शर्तों के तहत डिक्री नहीं है। इस मामले में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे नाथ प्रसाद बनाम राम पलटन राम और अन्य[1] मामले में श्री जस्टिस स्ट्रेट की टिप्पणियों से समर्थन मिलता है, हालांकि यह निर्णय कोर्ट-फीस के मामले से संबंधित नहीं है। विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियाँ नीचे उद्धृत की गई हैं;
«* * * किसी मुकदमे को मध्यस्थता के लिए भेजने का समझौता मुकदमेबाजी को बंद नहीं करता है; इसके विपरीत, पार्टियां वादी और प्रतिवादी की प्रतिकूल स्थिति में मध्यस्थों के समक्ष जारी रहती हैं, एक दूसरे पर दायित्व तय करना चाहता है, और दूसरा उस दायित्व से बचना चाहता है। भले ही फैसला बाद में पार्टियों की सहमति पर दिया गया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह मुकदमे में फैसले की स्वीकारोक्ति के लिए किसी भी तरह से अलग स्थिति में है, और किसी भी मामले में जो डिक्री पारित की गई है, प्रतीत होता है कि वह समान स्तर पर हैं। **** * * * * "

(6) इसलिए, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या डिक्री, जिसका पालन किया गया, एक मुकदमे में डिक्री थी; और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस डिक्री के बाद मुकदमा चला, वह डिक्री थी जिसने मुकदमे को समाप्त कर दिया; और, इसलिए, कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान लागू होते हैं।

(7) ऊपर दर्ज कारणों से, आपत्ति मान्य है और स्वीकार की जाती है। वादी को कोर्ट-फीस की भरपाई के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

[1] **आई.एल.आर. 4 इलाहाबाद 218.**

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कुरूक्षेत्र, हरियाणा